Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, GIF: 2.7282, CIF: 5.647, Volume 10, No. 01, January, 2020, pp. 277-282

वैश्वीकरण के दौर में भारत पर प्रभाव

उषा शर्मा*
श्रीमती डॉ. विजय सर्राफ**

परिचय

भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति का मिश्रित परिणाम है। इसके अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने की छूट होती है। जैसे कच्चा माल विश्व एक हिस्से में सस्ता मिलता हो, श्रम दूसरे हिस्से से सस्ता मिलता हो, पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हो और बाजार दूर दूर फैले हो तो यह प्रक्रिया भूमण्डलीकरण कहलाती है। इस में देशों की सीमाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए खोल दी जाती है। इस नीति को 1980 के दशक में विश्व में मान्यता मिली है। इसमें संचार क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में भूमण्डलीकरण की नीति ने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, परिवहन, संचार व राजनीतिक प्रणाली के परस्पर समन्वय के कारण सम्पूर्ण विश्व में एक 'वैश्विक ग्राम' का रूप धारण कर लिया है। इसमें व्यक्ति और संस्थाओं, कम्पनियों में पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अन्तःक्रिया को बढ़ावा मिला है।[1]

वैश्वीकरण से उत्पन्न व्यापक परिवर्तनों से हमारे जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिकता को सुसाध्य बनाया है और ज्ञानोदय ने मनुष्य के भ्रम से परदा उठाया है उसी तरह हम आज एक अन्य युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। पूंजीवाद, उद्योग और राष्ट्र–राज्य जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनका जन्म आधुनिकता के साथ हुआ, उनके स्वरूप में भी आज व्यापक बदलाव आ गया है। इस प्रकार वे जो भूमिका निभा रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। आज वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है। चीजों को नए प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है इसलिए उनकी पुरानी पहचान भी समाप्त होती जा रही है। आज वर्ग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक भूमि का विखंडन देखा जा सकता है जिसने कभी सामाजिक प्राणियों को दृढ़ता प्रदान की थी। यहां तक कि अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था के क्षेत्र में हम भावी खतरों का भी अनुमान नहीं लगा सकते है। हालांकि एक चीज निश्चित है कि हम वैश्वीकरण के लाभों को नहीं झूठला सकते। अतः वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे बंद करने की बजाय हमें इसके लाभ और हानि के मध्य प्रभावी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां व्यक्तिगत सरकारें कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। अतः यदि हमें वैश्वीकरण की समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका समाधान भी वैश्वीकरण से ही हो सकता है। भूमण्डलीकरण व वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। यह एक वैश्विक अभिशासन के नए रूप की मांग करता है जो सहयोग और कुशलता से वैश्विक मुद्दों का समाधान करेगा।

वैश्वीकरण की प्रकृति

वैश्वीकरण विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर एक–दूसरे से मतभेद रखते है। वे मुख्य ध्यान विश्व में एक व्यवस्था होने पर लगाते है। साथ ही उन वैश्विक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं जो कि समाज व राष्ट्रों से अलग

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।
** व्याख्याता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, राजस्थान।

व स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख क्रियान्वित होती हैं। इस तर्क के समर्थन में कि वैश्वीकरण से व्यक्ति व समाज दोनों अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं, रिट्जन तथा मॅलेन का मानना है कि मैकडानल्ड जैसे अमेरिकी उत्पाद उपभोक्तावाद की मानसिकता पर फल–फूल रहे हैं। साथ ही इससे लोगों को लगने लगा हें कि विश्व व्यवस्था में राज्य अब प्रमुख कारक नहीं रह गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रमुखता से अपनी जगह बना रही है। इसके साथ ही विश्व में विभिन्न स्थानों पर मैकडॉनल्डाइजेशन की प्रक्रिया के विरोध के भी संकेत मिलने लगे है। ऐसा मुख्य रूप से विकासशील देशों में हो रहा है। विकासशील देशों में लोग बड़ी संख्या में मानते है कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्वीकरण प्रक्रिया ने अमीरों को ही लाभ पहुँचाया है।

वैश्वीकरण से सम्बन्धित सिद्वान्त अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाए है, परन्तु इन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामरिक तथा संस्थागत रूपों में बाँटा गया है। वैश्वीकरण की अवधारणा नई नहीं है। यह प्रक्रिया तो प्राचीन समय से चल रही है इतिहासकार, साधु तथा राजा तब धन, शक्ति व ज्ञान की खोज में नए–नए मार्गो की खोज करते हुए दूर–दराज की यात्राएँ किया करते थे। इसका प्रमाण चीनी तथा फारसी लोगों की विभिन्न उद्देश्यों से दूर देशों की यात्रा से मिलता है। औद्योगिक क्रांति ने भी उद्योग तथा तकनीक से मानवीय संवाद व आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया। सूचना व संचार जगत् में आई क्रांति ने तो वस्तुओं, पदार्थो, तकनीकों, संसाधनों, विचारों और विशेषज्ञता के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। साथ ही यात्रियों व पर्यटकों के रूप में लोगों के आवागमन को भी बहुत बढ़ा दिया है। विंसेट वाइ चेंग वांग ने वैश्वीकरण की चार दशाएँ बतायी हैं–

- खोज व अन्वेषण का युग (1492–1789), जो कि व्यापार व प्राचीन भंडारण के रूप में सामने आया। इसका प्रतीक कोलम्बस द्वारा की ग यी अमेरिका की खोज को माना जा सकता है।
- क्रांति, मुद्रा व साम्राज्यों का युग (1789–1900), जिसकी झलक फ्रांसीसी क्रांति व ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की उत्पादन क्रांति से उपजे औद्योगिक साम्राज्यवाद से मिलती है।
- अतिवादी युग (1900–1970), प्रथम विश्वयुद्ध तथा रूस की बॉलशेविक क्रांति के दौरान एकाधिकारी पूँजीवाद इसका प्रतीक है।
- सूचना का युग (1970 से लेकर वर्तमान तक) यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रकट होता है । इसकी विशेष बात बर्लिन की दीवार का टूटना तथा सोवियत संघ का विघटन रही।

वैश्वीकरण आखिर क्या है तथा इसके प्रमुख घटक क्या है ? इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। शुद्ध रूप में वैश्वीकरण का अर्थ भोगोलिक सीमाओं का न होना तथा भौगोलिक दूरियों की समाप्ति माना जा सकता है। इसके तात्पर्य विभिन्न देशेां व व्यक्तियों से सम्बन्धित विचारों, तकनीकों, संस्कृतियों तथा अर्थव्यवस्थाओं के बीच घटती दूरियाँ व त्वरित आदान–प्रदान भी हैं इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उन बहुराष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। जिन्होंने विश्व समुदाय की चिन्ताओं व हितों को मुखर रूप से उठाया है।

शीतयुद्ध काल की समाप्ति व सोयिवत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण को लेकर विश्व में गर्म बहस छिड़ी हुई है। न्यूयार्क टाइम्स के विदेश मामलों के स्तम्भकार थॉमस एल. फ्रीडमन का मानना है कि, ''वैश्वीकरण व्यवस्था ने शीतयुद्धकालीन व्यवस्था की जगह ले ली है।'' फ्रीडमन समझाते है कि वैश्वीकरण ने बाजार व्यवस्था को बढ़ाया है। साथ ही इसने समान वैश्विक संस्कृति को भी पनपाया है जो मुख्य रूप से विश्वस्तर पर अमेरिकी संस्कृति का प्रसार ही है। वर्ष 1999 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक बाजार, वैश्विक तकनीक, वैश्विक विचार तथा वैश्विक एकता को बढ़ाकर सभी स्थानों पर आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना है। रिपोर्ट के अनुसार ''वैश्वीकरण के नये रूप का अर्थ नये बाजार, नये अभिनेता, नये नियम व प्रचलन तथा संचार की नई तकनीकों का प्रसार है।'' विश्व स्तर पर काफी हद तक हैन्स हैन्डरिक हॉल्स तथा जॉर्ज सोरेन्सन द्वारा दी गई वैश्वीकरण की परिभाषा को ही मान्यता मिली है। उनके अनुसार, वैश्वीकरण से तात्पर्य, ''विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के बीच, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है।'' इस परिभाषा के अनुसार, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों

तथा विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी नीतियों की प्रकृति को ही बदल दिया है। विश्वीकरण का दायरा अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्महाद्वीपीय भी माना जा सकता है। इसने राज्यों व सभाओं के बीच संवाद तथा आपसी सम्पर्को को भी बढ़ावा दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ वैश्वीकरण की प्रक्रिया से राष्ट्र/राज्यों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि उनका स्वायत्तता, अर्थव्यवस्था, मानवीय सुरक्षा व विकास से भी जूझने का प्रयास कर रहे है। विशेषज्ञ वैश्वीकरण प्रक्रिया के विभिन्न सभ्य समाजों, एशिया तथा लैटिन अमेरिका की अधिनायकवादी सरकारों व खाड़ी तथा मध्य पूर्व के तानाशाहों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे है।

वैश्वीकरण प्रक्रिया के बढ़ने का एक प्रभाव क्षेत्रीयवाद के पनपने के रूप में भी सामने आया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सदस्यों देशों के बीच एकीकरण भी बढ़ा हैं। क्षेत्रीयवाद शुरू में विश्व में स्थापित हो रही बड़ी आर्थिक शक्तियों जैसे यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया में और आर्थिक विकास की इच्छा के परिणामस्वरूप पनपा था। बाद में क्षेत्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं ने विभिन्न आकार लिये तथा विश्व के विभिन्न भागों में अलग–अलग तरह से व्यापार प्रक्रिया विकसित होती गई। इसका संकेत, पश्चिमी यूरोप में बढ़ रहे आर्थिक संरक्षणवाद से भी मिलता है। यह संरक्षणवाद विकासशील देशों की कीमत पर एकीकृत स्थायी व खुशहाल यूरोप स्थापित करने की दिशा में था। यूरोपीय संघ में व्यापार नियमों व व्यवस्थाओं का विकासशील राष्ट्रों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। विकासशील राष्ट्र भेदभाव सहित व्यापार व्यवस्था चाहते हैं। इसके बावजूद भी, क्षेत्रीयवाद का विश्व व्यवस्था में व्यापार, निवेश, पूँजी आधारित तकनीक के हस्तांतरण व कूटनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

वैश्वीकरण : भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैश्वीकरण के युग में विश्व अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर दौर से गुजर रही है। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं बेड़ी विहीन पूंजीवादी बाजार व्यवस्था ने विकासशील, समाजवादी एवं अर्द्ध विकसित देशों को संदेश दिया कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ी है। यह तर्क भारत तथा चीन जैसे घनी आबादी के देशों को आश्वस्त करने लगा जिसके अंतर्गत चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया। विकास के समाजवादी मॉडल को त्यागकर पूंजीवादी बाजार की अर्थव्यवस्था को ग्रहण किया। निःसंदेह, आर्थिक उदारीकरण एवं संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को ऊंचाईयाँ प्राप्त हुई। वर्तमान में इन दोनों देशों की सबसे तेजगति से चलने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, यद्यपि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण इनकी आर्थिक वृद्धि की दर में गिरावट अवश्य आई है। जहाँ चीन की आर्थिक वृद्धि की दर 12 प्रतिशत हुआ करती थी वह 2015 में 6.9 प्रतिशत रह गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आई आर्थिक मंदी का प्रभाव चीन पर पड़ा है। अमेरीका सबसे बड़ा चीन का आयातक देश है। अमेरिका व यूरोप जो चीनी वस्तुओं के सबसे बड़े आयात करने वाले देश थे, उन्होंने चीन से भारी मात्रा में आयात कम कर दिया है। इसका सीधा दुष्प्रभाव चीन के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में चीन की आर्थिक विकास की दर सन् 2016 में 63 प्रतिशत और सन् 2017 में 6 प्रतिशत अनुमानित थी।

वैश्विक आर्थिक संकट नया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट की पुनरावृत्ति है। 1980 के दशक में मेक्सिको में ऋण संकट पैदा हुआ; 1990 के अंतिम दशक में रूस और पूर्वी एशिया के देशों में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। इन संकटों को ध्यान में रखते हुए जी–7 की सरकारों, ब्रेटनवुड्स संस्थाओं और अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों ने वित्तीय व्यवस्था को दुरस्त बनाने के लिए विश्व बाजारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों की वकालत की गई। उधार व्यवस्था पर बैंक के नियमन व्यवस्था एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत के बड़े–बड़े राष्ट्रीय बैंकों ने (17 बैंकों) उद्योगपति विजय माल्या को 9 हजार करोड़ की रकम जो उधार दे रखी थी उसकी माल्या से वसूली नहीं की जा सकी है। बैंकों ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का

दरवाजा 5 मार्च, 2016 को खटखटाया। जबकि माल्या 2 मार्च, 2016 को ही भारत छोड़कर लंदन चले गए और वहीं से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया (मई 2016 में)। सी.बी.आई. और इन्फोसेमेंट डायरेक्टरेट (ईडी) उन्हें नोटिस जारी कर चुके हैं परंतु माल्या के पीछे राजनीतिक दलों और नौकरशाहों एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के कारण बैंकों के ऋण की वसूली नहीं हो पाई है। माल्या की किंग फिशर हवाई कंपनी जब घाटे में चल रही थी तब भी बैंकों ने माल्या को ऋण स्वीकृत करने में संकोच नहीं किया। इसी तरह ललित मोदी ने करोड़ों के घोटालों के बावजूद वह भी एक भगोड़े की तरह लंदन में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बैंकिंग संकट के पीछे बड़ा कारण नियमों की अवहेलना एवं नियामक व्यवस्था के दुरुस्त व चुस्त न होने से राष्ट्रीय वित्तीय संकट वैश्विक वित्तीय संकट में बदल जाता है।

2007 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण एवं हाउसिंग बाजार में अपर्याप्त इक्विटी के विरूद्ध में अधिकाधिक उधार देने की बैंकों की प्रवृत्ति से अमेरिका 2008 में आर्थिक संकट की चपेट में आ गया जिसके दुष्परिणाम विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झेलने पड़ रहे हैं।

- आइसलैण्ड पहला देश है जो वैश्विक आर्थिक संकट का शिकार हुआ। उसकी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई अर्थात् गिर गई जिसके कारण आइसलैण्ड की सरकार को उन्हें दिवालिया होने की घोषणा करनी पड़ी।
- अमेरिका और यूरोप में कई बैंकों को बन्द करना पड़ा; कई धन्धों के खर्चों में कटौती करनी पड़ी एवं वर्क फोर्स (कामकाजी लोग) को कम करना पड़ा; एवं बेरोजगारी के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई।
- वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दर 2015 में 3.1 प्रतिशत थी। अब आशा व्यक्त की जा रही है कि विश्व अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार के कारण 2016 में आर्थिक वृद्धि की दर 3.4 प्रतिशत एवं 2017 में 7.2 प्रतिशत आंकी गई है। सन् 2018 में 6.9 प्रतिशत रही।
- चीन की अर्थव्यवस्था की भी गति धीमी हुई है। भारत इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, रूस, नाइजीरिया तथा वेनेज्यूला की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- अमेरिका की मौद्रिक नीति में कठोरता आई है।
- लेटिन अमेरिका में ब्राजील व अन्य देशों में मंदी का प्रभाव वहाँ रोजगार एवं नौकरियों पर पड़ा है। लेटिन अमेरिका के अनेक देशों में हड़तालें व हिंसा का दौर चल रहा है।
- चीन के 'खराब कर्ज' जो + 5 ट्रिलियन को पार कर सकता है, चलते चीनी बैंकों ने ऋण देने से हाथ खींच लिए हैं।
- अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश बन गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जर्मनी, जापान और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ अमरीकी मांग पर निर्भर करती है।
- यूरोप ऋण संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल व इटली कंगाली की स्थिति में आ गये हैं। मार्च, 2016 में ब्रसल्स में यूरोपियन परिषद की बैठक में ईयू के नेताओं ने ऋण–ग्रस्त सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग पर बल दिया।
- भूराजनीतिक तनावों, संकट व गृह युद्धों का वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए जी–7, जी–20 तथा जी–5 के सदस्य देशों को वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए निम्न वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है –

- विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था एवं नियमों में सुधार लाना।
- वैश्विक वित्तीय नियामक व्यवस्था को विकसित कर उसके नियमों को कठोरता से लागू करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रो कोष में सुधार तथा आई.एम.एफ. के संसाधनों को तीन गुना वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है ताकि जरूरतमंद अफ्रीकी देशों के ऋण व अनुदान से अधिक दिया जाये।

वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मत है कि ''अनियंत्रित वैश्वीकरण'' वांछित नहीं है। अतः नई संस्थाओं और क्षतिपूर्ति व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि वैश्वीकरण को प्रभावी एवं टिकाऊ बनाया जा सके। सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती नवीन संस्थाओं का तंत्र विकसित करना है। नवीन वैश्वीकरण की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से किया जायेगा कि क्या वैश्विक आर्थिक उदारीकरण से विश्व के अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है या नहीं तथा गरीब व अमीर के बीच की खाई कम हुई है या नहीं। क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाये गये सुधारों से एक न्यायोचित एवं पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है ?

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप आई क्रांति ने विश्व/वैश्विक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इन्टरनेट के माध्यम से लोग एक–दूसरे से तीव्र गति से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंकडइन एवं अन्य माध्यमों से संपूर्ण विश्व के लोग एवं विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं आस्थाओं एवं विचारधारों से प्रेरित लोग एक–दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जुड़ने की प्रक्रिया ने लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच में भारी परिवर्तन आया है। भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि यहाँ का समाज तीव्र गति से बदल रहा है।

वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव

भारत ने जून 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया था। देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था निर्यात–आयात व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए आर्थिक उदारीकरण अपरिहार्य हो गया था इसके प्रभावों को निम्नानुसार बतलाया जा सकता है –

- औद्योगिक लाइसेंस राज को कुछ अपवादों को छोड़कर समाप्त करना;
- निर्यात को बढ़ावा देना;
- विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना;
- पब्लिक–प्राइवेट साझेदारी को आगे बढ़ाना ताकि देश की आर्थिक विकास की गति में अभिवृद्धि, निरंतरता एवं स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- आर्थिक उदारीकरण की गति को बनाये रखना।

उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि हुई है वहीं आर्थिक मूलभूत ढांचे में बदलाव के कारण विशेष रूप से सड़क, मोटर परिवहन, रोजगार, टेलीकम्यूनिकेशन, इन्सश्योरेंस, एयरपोर्ट आदि क्षेत्रों में आशातीत व सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लेकिन आर्थिक व्यापारिक उदारीकरण के ऋणात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उनमें (1) वैश्विक प्रतिद्वंद्वता के फलस्वरूप विदेशी कम्पनियाँ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत के घरेलू बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। भारत में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कुछ कार कंपनियों जैसे फियट, एम्बेसेडर पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिएट कार के उत्पादन को बंद करना पड़ा। (2) भारतीयों में विदेशी ब्रांड का असर बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी के लोग छोटे–मोटे काम जैसे कॉल सेंटर्स से पैसा कमाकर विलासिता की वस्तुओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं। (3) लोकल बाजारों में भारतीय माल के प्रति रूझान कम होता जा रहा है। (4) भारत का उद्योग श्रम प्रेरित था वह पूंजी–प्रेरित होता जा रहा है। (5) कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। (6) बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। (7) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अंधाधुंध विस्तार से अनुसंधान व गुणवत्ता शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2016 की प्रिसंटन मूल्यांकन के अनुसार भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, केवल प्रबंधन संस्थाओं को छोड़कर, टॉप 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव

- भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का त्यागकर भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की ओर आकृष्ट होता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं; संयुक्त परिवार की प्रथा तेजी से गायब होती जा रही है; न्यायालयों में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
- अंतर्जातीय विवाह एवं लिव–इन–रिलेशनशिप का फैशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन नये प्रयोगों का कुछ लाभ भी है परंतु उनके नुकसान अधिक हैं।
- भारत की प्रतिभा विदेशों की ओर रूख कर रही है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन गेडिस का मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक टूटन को जन्म दिया है; सामाजिक स्थिरता एवं सामुदायिक सौहार्दता को तार–तार करता है। निःसंदेह सांस्कृतिक विविधता जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है उस पर साम्प्रदायिक शक्तियाँ हावी होती जा रही हैं। जिनका उद्देश्य सांस्कृति पहनावा को थोपना है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा भारत जैसे देश में विविध धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों के लोगों में देश भावना, राष्ट्रीय प्रेम के प्रति मोह भंग हो सकता है। इससे भारत की एकता व अखण्डता को खतरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ✓ सिंह एस.एनः राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.सं. 213
- ✓ विस्वाल तपन (संपा): अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 356
- ✓ गिन्डसें, ए.: दी कोन्सेक्यूऐन्स ऑफ मोर्डेनिटी, केम्ब्रिज पोलिटी प्रेस 1990, पृ.सं.14
- ✓ हार्वे. डी.: दी कन्डीसन ऑफ पोस्ट मोर्डेनिटी ऑक्फोर्ड : कोंसिल ब्लेक व्हेल 1989 पृ. सं. 284
- ✓ आर्चर एम.एस.: सोसियोलोजी फॉर वन वर्ल्ड यूनिटी एण्ड डायवर्सिटी : इंटरनेशनल सोसियोलोजी वोल्यूम–6, संख्या–2, 1991, पृ.सं. 131–147
- ✓ कैगली एण्ड विटकॉफः वर्ल्ड पॉलिटिक्सः ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ. 118–121
- ✓ यूडरी क्रिस्टो, जेन्डर एग्रीकल्चर पोडेक्शन एण्ड दी थ्यौरी ऑफ दी हाउसहोल्ड, जनरल ऑफ पोलिटिकल इकोनोमी, वाल्यूम–104, संख्या–5, 1996
- ✓ बेलो, वाल्डेनः दी ग्लोबलाइजेशनः आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, लंदन जेड बुक्त, 2002
- ✓ सेन अमृत्यः हाउ टू जज ग्लोबलाईज्म, दी अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, वाल्यूम–13, संख्या–1, जनवरी 2002, पृ. सं. 1–14
- ✓ जोसेफ स्टिगलिट्सः ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेंट्स न्यूयार्कः डब्ल्यू डब्ल्यू एण्ड कम्पनी 2002
- ✓ भगवती जगदीशः इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस–2004

♦❐♦